

जनकल्पणा समाचार

ठाणे | वर्ष - २३ | अंक - १० | २५ से ३१ मार्च २०२४ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

लोकसभा चुनाव में टिकीट को लेकर शिंदे-अजीत में घमासान

जेकेएस संवाददाता

मुंबई, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी प्रमुख दल इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन महायुति में शामिल सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजीत पवार की राकां पार्टी के अन्दर चल रही आपसी कलह से जूझ रही है। शिंदे गुट के पूर्व में भारी नाराजगी है। ऐसा लग रहा है कि डिप्टी सीएम बारामती में अपने चाचा शरद पवार द्वारा बिछाई गई बिसात में पंस गए हैं। इस सीट से अजीत की योजना मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी



सुनेत्रा पवार को उतारने की है। लेकिन शिवतारे ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर अजीत की राह को मुश्किल बना दिया है। शिंदे ने शिवतारे को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वे चुनाव लड़ने की जिह पर अडे हुए हैं। इन तमाम विवादों की बजह से शिंदे और अजीत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पछड़ गए हैं। एक और जहां पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की है।

संपादक सीमा गुप्ता

पक्षपातपूर्ण व्यवहार

निर्वाचन आयोग को यह भरोसा कायम करना होगा कि हटाए गए अधिकारियों की जगह जिहें नियुक्त किया गया है, वे वास्तव में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिवों को भी हटाने का आदेश दे दिया। अब इस फैसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल सरकार इसे लेकर पक्षपात का आरोप लगा रही है।

हालांकि चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले ही निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने अपने पद पर तीन वर्ष का समय पूरा कर लिया है या जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं। मगर राज्य सरकारों ने उस निर्देश पर अमल नहीं किया था। उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं चाहती थी कि उसके गृह सचिव को हटाया जाए, मगर निर्वाचन आयोग ने उसकी दलील नहीं मानी। छिपी बात नहीं है कि चुनाव में शीर्ष अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। गृह सचिव राज्यों में और जिलाधिकारी जिलों में निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए अगर वे निष्पक्ष नहीं होंगे, तो उन जगहों पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही। इसलिए निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त को हटा दिया। हालांकि यह न तो पहली बार हुआ है और न कानून की नजर में कोई गलत कदम है। जहां भी निर्वाचन आयोग को लगाता है कि कोई अधिकारी चुनाव में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा सकता या निभा रहा, तो वह उसे हटा कर उसकी जगह दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। राजनीतिक दलों की शिकायतों के महेनजर चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी कई बार अधिकारियों को बदल दिया जाता है। अभी जिन राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त को हटाया गया, उनके बारे में पहले से राजनीतिक दल शक जाहिर कर रहे थे। उनकी संबंधित राज्य सरकारों के प्रति अधिक निष्ठा देखी जा रही थी। पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त तो काफी समय से विवादों में थिए थे। उनके खिलाफ सीधी आइने शिकंजा कसने की कोशिश की थी, तब मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ गई थीं। ऐसे में भला उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता था कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग करेंगे, राज्य सरकार की मर्जी के अनुरूप काम नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को लेकर भी इसी तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं। ऐसे समय में, जब विपक्षी दल मतदान मरीजों में गडबडी की आशंका जाती हुई अंदोलन पर उत्तर दुए हैं, बड़े जन सुमुद्रा में भी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह फैला हो गया है, तब ऐसे अधिकारियों को उनके पद पर बनाए रखना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता, जिनका आचरण संदिग्ध माना जाता रहा है। मगर केवल इतने भर से चुनाव में निष्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित नहीं हो जाती।

भाईंदर : नवघर पुलिस ने एक शातिर रिक्शा चोर को गिरफ्तार किया है। जो राह चलते रिक्शा की चोरी कर फरार हो जाया करता था। वे ही नहीं रिक्शे का सीएनजी या पेट्रोल जहां पर खत्म हो जाया करता था। उस रिक्शे को वहीं पर छोड़कर के दूसरी रिक्शा की चोरी कर फरार हो जाया करता था। साथ ही रिक्शा चोरी कर चलाया करता था। रिक्शा चलाने से जो भी पैसे मिलते थे। उससे वह अपना जीवन यापन करता था। रिक्शा चोर इतना शातिर है कि किसी भी मास्टर के बजाय रिक्शा की चोरी कर कुछ ही मिनट में फरार हो जाया करता था। नवघर पुलिस के द्वारा रिक्शा को लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तांत्रिक विशेषज्ञ और सूत्रों की मदद से नवघर पुलिस ने आरोपी को एमएच बुलिस स्टेशन के ७ केस डिटेक्ट हुए। नगर पुलिस की जांच में रिक्शा चोरी की जांच नवघर पुलिस कर रही थी। चोरी के स्थान के सीसीटीवी की जांच में एक व्यक्ति रिक्शा को लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तांत्रिक विशेषज्ञ और सूत्रों की मदद से नवघर पुलिस ने आरोपी को एमएच कॉलोनी बोरीवली पश्चिम मंडपेश्वर मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शशिकांत बरामद को आरोपी को एमएच बुलिस के ७ केस डिटेक्ट हुए। नगर पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी मुंबई में रिक्शा चोरी के मामले में सजा काटकर आया हुआ है। नवघर पुलिस आरोपी से यह जांच कर ही है कि आरोपी और कहा कहा रिक्शा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई
भाईंदर। उचित सम्मान को लेकर भाजपा के कार्यकार्ता आपस में ही भिड़ गए। ऐसे चलते लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई सुपर वॉरियर्स विधायक नरेंद्र मेहता के नाम और काम की बैठक रद्द कर दी गई। धक्का - मुक्की, कहासुनी, हाँगामा और नारेबाजी का बीड़ियो वायरल है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार की रात ब्लूमून क्लब में भारतीय गुलबागा कर्नाटक है। आरोपी से जिक्र न करने पर आपत्ति जाताई है।

खेल के मैदान खेल का ही रहना चाहिए - विधायक प्रताप सरनाईक

भाईंदर : भाईंदर के उत्तर चौक क्षेत्र के एकमात्र प्रमुख खेल के मैदान पर हेलीपैड के निर्माण पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने इस गांव का दौरा किया। विधायक सरनाईक ने खेल मैदान में हेलीपैड बनाने का विरोध किया है और जिला कलेक्टर से चर्चा की जा रही है। वहीं, विधायक सरनाईक की मांग मान ली गई है। शिव सेना की ओर से उत्ताप्त अधिकारियों का हस्ताक्षर अधिकारी परिसर में बनाने की विधायक सरनाईक आज स्थानीय नागरिकों की राय और स्थिति जानने के मोके पर पहुंचे थे। चौक के इस मैदान में किंकट और अन्य खेल खेल जाते हैं। लेकिन यहां की कौली महिलाएं अप्रैल और मई में यहीं खेलना सुखाती हैं।

खेल का मैदान खेल का मैदान ही रहना चाहिए, ऐसा विधायक सरनाईक ने कहा। विधायक सरनाईक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से खिलाफ जिक्र किया है। विधायक सरनाईक ने काम रोक दिया है। विधायक सरनाईक ने इस संबंध में भारतीय नागरिकों की राय और स्थिति जानने के मोके पर पहुंचे थे। चौक के इस मैदान में किंकट और अन्य खेल खेल जाते हैं। लेकिन यहां की कौली महिलाएं अप्रैल और मई में यहीं खेलना सुखाती हैं।

इसलिए यहां कोई हेलीपैड नहीं होना चाहिए है, भविष्य में कोई सरकारी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इस खेल के मैदान को खेलने के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। विधायक सरनाईक ने काम रोक दिया है। चौक, याती, उत्तन, डोंगरी, तरोडी पंचकोटी खेल के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण खेल का मैदान है और यहां विभिन्न खेल और क्रिकेट मैच आयोजित किए जाते हैं। निर्णय बनाने के अधार पर उत्तन चौक पर ना बन कर ये हेलीपैड डोंगरी में बनेगा।



और मंच पर चढ़ कर हंगामा शुरू किया जाता है। इसके बाद दोनों युगों के बीच कहासुनी हुई थी। कोई बड़ा मामला नहीं है। जबकि व्यास गुट के कार्यकारिणों ने बोहरा के हाथ से माइक छिनने की कोशिश की। इसके पहले भी दो-तीन बार जानकारी मिली थी कि एक सिल्वर रंग की सेवरोलेट कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार ड्राइवर को रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर कार लेकर भागने लगा था।

HAPPY BIRTHDAY
आशा कोहले
समाजसेविका
जाजीन
की हार्दिक बधाई एवं फेर सारी
शुभकामनाएं

३० मार्च

निलेश सोनी
सीमा गुप्ता
बीजेपी

संपादक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाई राजा, प्रदीप शर्मा को उम्र कैद



जेकेएस संवाददाता

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को २००६ बैठक राजानारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया वें पर्फर्ज एनकाउंटर केस में दोषी माना। कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। गैंगस्टर छोटा राजन का करीबी बताकर गुप्ता वें एनकाउंटर मामले में शर्मा को सत्र न्यायालय वें सफलतापूर्वक द्वारा मामले में सत्र न्यायालय द्वारा मामले में १३ आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। वहीं दोषी ठहराए गए छह लोगों को बरी कर दिया है। हालांकि अभी भी दोषी पुलिसकर्मियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। २०१३ में नियती अदालत ने बैठक वें २२ में से २१ आरोपियों को दोषी ठहराया था, वहीं शर्मा को सबूतों वें अभाव में मामले से बरी कर दिया था। २१ में से दो आरोपियों को हिरासत वें दौरान मौत हो गई थी। इसलिए उनवें मामले को प्रकरण से अलग कर दिया गया था। शर्मा की रिहाई वें खिलाफ राज्य सरकार और गुप्ता वें भाई हाई कोर्ट में अपील की थी, जबकि दोषियों ने सजा वें पैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। १८ नवंबर २०२३ को बैच ने लंबी सुनवाई वें बाद पैसले को सुरक्षित कर लिया था।

न्यायालय वें पैसले पलटकर में सत्र न्यायालय द्वारा मामले में शर्मा को १८ साल बाद सालाहों के पीछे भेज दिया है। कोर्ट ने शर्मा को हत्या, अपहरण और आपाराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराया है। शर्मा एंटीलिया केस में भी आरोपी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले में उन्हें जमानत दी थी लेकिन हाई कोर्ट वें इस फैसले के बाद शर्मा फिर जेल ढेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने शर्मा की रिहाई को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया। बैच ने कहा कि सेशन कोर्ट ने शर्मा वें खिलाफ उपलब्ध पर्याप्त और ढेरों सबूतों की अनदेखी की है। सबूतों की लंबी कड़ी प्रकरण में शर्मा की सलिलतात को पूरी तरह से साबित करती है। बैच ने मुंबई पुलिस के चर्चित अधिकारी रहे शर्मा को तीन हफ्ते वें अंदर सत्र न्यायालय वें सामने संदेश दिया है। १८ दिनों के फैसले में बैच ने मामले

राजनीतिक दलों के नाम पर ठगी का व्यापार

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : आग आपके सोशल मीडिया मंच (फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर किसी फौजी या पुलिस अधिकारी का वर्दी वाला फोटो और कम दाम पर घरेलू सामान बेचने की बीमत पर मंहगे सामान बेचने की बात करेगा और प्रेमेंट ऑनलाइन देने का निवेदन करेगा। अगर आप भी ऐसे किसी फौजी या नेताओं के करीबियों के चक्रकर में फंसे हैं, तो वह यहुंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस को दें और इन फर्जी लोगों से दूर रहें। चारकोप पुलिस ने

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के विभाग प्रमुख दिनेश साल्वी का

पुलिस के अनुसार, साल्वी का फोटो वाला डीपी के आधार पर फर्जी फेसबुक एकाउंट बना कर उसके

परिचितों से धन मांगने की शिकायत साल्वी ने की है। एक अधिकारी ने बताया कि साल्वी का फोटो यूज कर नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों का ठगने का केस दर्ज किया है।



पुलिस के अनुसार, साल्वी का फोटो वाला डीपी के आधार पर फर्जी फेसबुक एकाउंट बना कर उसके

